



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 सितम्बर, 2007 / 3 आश्विन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2007.

संख्या:गृह-सी(ए)3-7/2006-V.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में सहायक निदेशक (डी.एन.ए) वर्ग-। (राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में सहायक निदेशक (डी.एन.ए) वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
एस विजय कुमार,
प्रधान सचिव।

**हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक (डी.एन.ए)
वर्ग— I(राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम**

1. पद का नाम : सहायक निदेशक (डी.एन.ए)
2. पदों की संख्या : 02 (दो)
3. वर्गीकरण : वर्ग— I(राजपत्रित)
4. वेतनमान : 10,025—275—10,300—340—12,000—375—13,500—400—15,100 रूपए
5. चयन पद अथवा अचयन पद: चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश/(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्व ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं:

(क) अनिवार्य अर्हता :— (i) डी0एन0ए0 विश्लेषण/रूपरेखा में विशेषज्ञता के साक्ष्य सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आणविक जैविका मौलीक्यूर बायोलॉजी/मापव जैविकी (हयूमन बायोलॉजी)/मानव अनुवंशिकी/(हयूमन बायोटेक्नोलॉजी)/सूक्ष्म जैनेटिक्स)/बायो प्रौद्योगिकी जैविकी (माइक्रो बायोलॉजी)/न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला/भौतिकी मानव विज्ञान (फिजीकल एन्थ्रोपोलोजी)/जीव रसायन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) की उपाधि या इसके समकक्ष ।

(ii) उपरोक्त या सहबद्ध किसी एक विषय में डी0एन0ए0 में शोध प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक कार्य में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) के उपरान्त सात वर्ष का अनुभव/पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए किए गए शोध कार्य की गणना कुल अनुभव में की जाएगी।

वॉछनीय अर्हता :- 1. न्यायालयिक प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव।

2. हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान वशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :- आयु: लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता: हॉ जैसा उपरोक्त स्तम्भ संख्या:7 के सामने विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :- (i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, या संविदा आधार पर।

(ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :- विशिष्ट खण्ड के वैज्ञानिक अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिसका पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर भारत में केन्द्रीय/राज्य न्यायलिक प्रयोगशालाओं में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमेंट आधार पर।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :- यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :- विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :- सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:-

(1) **संकल्पना :-** (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आना :-** सचिव (गृह), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(11) **संविदात्मक उपलब्धियां :-** संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) को 15038 रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के

बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 400/—रूपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :- सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :- संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :- अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) को 15038/—रूपये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 275/—रूपए की दर से (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव

होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

- (ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII)नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :- इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण :- सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा :- सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति :- जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध— "ख"

सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार निदेशक के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.....रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त(पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) (पद का नाम) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) (पद का नाम) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त सहायक निदेशक (डी0एन0ए0) (पद का नाम) कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C(A) 3-7/2006-V dated 30-8-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

DEPARTMENT HOME

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th August, 2007

No. Home-C(A)3-7/2006-V.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Assistant Director (DNA), Class-I (Gazetted) in State Forensic Science Laboratory, Home Department, Himachal Pradesh as per Annexure “A” attached to this notification namely;-

1. *Short title and commencement:-* (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Assistant Director (DNA), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.

(2) These Rules shall come in to force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

By order,
S. VIJAY KUMAR,
Principal Secretary.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR (DNA), (CLASS-I GAZETTED), IN THE STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY, HOME DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. *Name of Post* : Assistant Director (DNA)
2. *Number of Post* : 02 (Two)
3. *Classification* : Class-I (Gazetted)
4. *Scale of Pay* : Rs. 10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100
5. *Whether Selection post or Non-Selection post* : Selection
6. *Age for direct recruitment* : Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes /Scheduled Tribes /Other backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in public sector Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations /Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations /Autonomous Bodies after initial constitution of the public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for Inviting applications or notified to the employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the H.P Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified

7. Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruits:-

Essential Qualification: - (I) At least 2nd Class Mater's Degree in Molecular Biology / Human Biology /Human Genetics /Bio-Technology /Microbiology /Forensic Science /Physical Anthropology / Bio-Chemistry or equivalent from a recognized University with evidence of specialization in DNA analysis /Profiling.

(II) Seven years post M.Sc.experience in DNA research training and analytical work. Research work done for doing Ph.D.Degree shall be counted in total experience.

Desirable qualification:- 1. Ph.D Degree with experience of working in DNA Division of a Forensic Science Laboratory.

2. Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees :

Age : Not applicable.

Educational qualification : Yes, as prescribed against Co.No.No.7 above.

9. *Period of Probation, if any :-* Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods :-* (i) 50 % by direct recruitment or on contract basis.

(ii) 50% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment or on contract basis.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion /transfer is to be made :-* By promotion from amongst the Scientific Officers of particular division with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which on secondment basis from the incumbents of this post working in the identical pay scale from Central/State Forensic Science Laboratories in India.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service /appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions happened to be Ex-servicemen recruited under the provision of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? :-* D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

13. *Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment :-* As required under the law.

14. *Essential requirements for a direct recruitment :-* A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment :-* Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus, etc, of which, will be determined by the Commission /other recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment:—

- (I) **CONCEPT :-** (a) Under this policy, the Assistant Director (DNA) in the State Forensic Science Laboratory of Home Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.
- (b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PUBLIC SERVICE COMMISSION:-** The Secretary (Home) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
- (d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS :-** The Assistant Director (DNA) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.15,038/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.275/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY :- The Secretary(Home), H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS :- Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:-
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT :- After selection of a candidate, he /she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :- (a)The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.15,038/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale+ dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.275/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

- (b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. (c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.
- (d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He /She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- (e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (g) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his /her official duties at the same rate as applicable to Regular Officials at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:- The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization /permanent absorption as Assistant Director (DNA) in the Department at any stage.

16. Reservation :- The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes/ other Backward Classes / Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination :- Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997.

18. Powers to Relax :- Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract /agreement to be executed between the Asstt. Director (DNA) (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____. Between _____ Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Asstt. Director (DNA) (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Asstt. Director (DNA) Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso facto stand terminated on the last working day i.e. on _____. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. _____ per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual Asstt. Director (DNA) (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Asstt. Director

(DNA)(Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Asstt. Director (DNA) (Name of the post) will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over.The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer /Practitioner.
9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF /GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

HOME DEPARTMENT
SECTION-D

NOTIFICATION

Shimla-2, 10th September, 2007

No. Home-D (B-6)-1/2007. — The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the transfer and posting of Sh. Ved Prakash, HPS, Dy.S.P. 3rd IRB, Pandoh as Dy.S.P. 2nd IRB, Sakoh, Dharamshala, against vacant post, with immediate effect in the public interest.

By order;
Sd/-
Chief Secretary.

“HOME DEPARTMENT”

Shimla, the 4th August, 2007

Corrigendum

File No. Home (A) A (3)-1/2005:— In appendix-12.12A annexed with this Department's Notification No. Home (A)A(3)-1/2005 dated 14-03-2007 regarding amendment in Recruitment Procedure to Police Battalion in Punjab Police rules, 1934 the entries against Sr. No.-7 of the table contained in Para- 4-**Eligibility** (Page-3) may be read as under:-

Sr. No.	Category	Age	Education	Height		Chest (for male Candidate only)
				Male	Female	
7.	Distinguished Sportsmen (SC/ST)	18 to 25 Yrs.	10+2	5' 4"	5' 0"	29"x30"

By order,
S. VIJAY KUMAR
Principal Secretary.

“HOME DEPARTMENT”

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th September, 2007

No. Home(A)B(1)-3/2007:— The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee and in pursuance of the instructions of Department of

Personnel, Govt. of H.P. No. Per(AP)C-F(1)-1/2002 dated the 6th October, 2006 is pleased to order the promotion of Shri Ram Dass, Supdt. Gr.-I, to the post of Administrative Officer, Class-I (Gazetted) in the pay scale of Rs.7880-11660, in the Police Department, Himachal Pradesh on regular basis with immediate effect.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining.

He will be eligible to exercise his option for fixation of pay under the provisions of FR 22(1)(a)(1) within one month from the date of issue of this notification.

This promotion will however, be subject to the final outcome on the Writ Petition (Civil) No. 61/2002 titled M. Nagaraj & Ors. V/S Union of India & others and Writ Petition (Civil) No. 295/2002- titled Devi Ram Tanwar & Ors. V/S Union of India & Ors. in the Hon'ble Supreme Court of India.

By order,
S.VIJAY KUMAR,
Principal Secretary.

“HOME DEPARTMENT”

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th September, 2007

No. Home(A)B(2)-4/2006:— The Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Shri Braham Dass, Superintendent Gr.-II to the post of Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted), in the pay scale of Rs. 7220-11660, in the Police Department, Himachal Pradesh on regular basis with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is, further pleased to order the posting of Shri Braham Dass, Superintendent Grade-I in Police Headquarters, Shimla.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining.

He will be eligible to exercise his option for fixation of pay under the provisions of FR 22(1)(a)(1) within one month from the date of issue of this notification.

This promotion will, however, be subject to the final outcome on the Writ Petition (Civil) No. 61/2002, titled M. Nagaraj & Ors. Vs. Union of India & Ors. and Writ Petition (Civil) No. 295/2002- titled Devi Ram Tanwar & Ors. Vs. Union of India & Ors. in the Hon'ble Supreme Court of India and also subject to final outcome of the OA No. 35/2001 pending in Hon'ble Tribunal.

By order,
S.VIJAY KUMAR,
Principal Secretary.

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 17th September, 2007*

No. Home-B (B)15-10/2005-HC.— In exercise of the powers vested in him under Sub Section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint the following Officers to be the Executive Magistrates with the powers of Executive Magistrate under the said code to be exercised within the local limits as shown against their names with immediate effect, subject to the conditions as contained in the Home Department's Himachal Pradesh Government letter No. Home-B (B)-12-5/84 dated 4-12-84 & 28 12-84. They shall cease to function as Executive Magistrate on their transfer out of this jurisdiction.

Sr.No.	Name of Officer and Designation	Jurisdiction
1.	Shri Atma Ram Sangta, Tehsildar (Recovery)	Tehsil Shimla
2.	Shri Kali Ram Harjiuta, Naib-Tehsildar	Tehsil Kotkhai

By order,
Sd/-,
Pr. Secretary.

HOME DEPARTMENT (PROSECUTION)**NOTIFICATION***Shimla-2, the 13th August, 2007.*

No. Home (Prose.)B(8)1/07:— The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that the following Joint Directors, Prosecution have satisfactorily completed the probationary period of two years on the date shown against their names:-

S.No.	Name of Officer	Date of completion of two years of probationary period.
1.	Jt. Directors (P) S/Shri H.S. Rana	12.1.06
2.	Satish Chander	12.1.06
3.	Anirudh Singh	12.1.06
4.	Raghu Raj Singh	28.12.06
5.	Kushal Singh	15.2.2007
6.	Jawahar Lal Sharma	2.4.2007

By order,
Sd/-,
Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA.-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 14 September, 2007*

NO.HHC/GAZ/14-53/74-V.-—Consequent upon his appointment to the HP Judicial Service in the cadre of District/Additional District & Sessions Judges, vide Notification No. Home-B (B) 2- 11/2006-HC, dated 12.9.2007, issued by the Government of Himachal Pradesh, Hon'ble High Court is pleased to post Shri Chirag Bhanu Singh as Additional District and Sessions Judge, Solan, against a vacant post with immediate effect.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA.-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 15 September, 2007*

No.HHC/GAZ/14-99/80-II.— The Hon'ble High Court has been pleased to extend the period of probation of the following members of the H.P.Judicial Service, in the cadre of Civil Judges (Jr. Division) under Rule 10(3) read with Rule 18 of H.P.Judicial Service Rules, 2004 for one year with effect from the date(s) shown against each or till they qualify the Departmental Examination, which ever is earlier:-

Sr. No.	Name of the Officer	Date from which probation period is extended.
1.	Smt. Sheetal Sharma	30.7.2007
2.	Shri Basant Lal Verma	31.7.2007

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA.-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 17th September, 2007*

No.HHC/GAZ/10-40/80-IV.-—Consequent upon the enactment of the H.P.Judicial Officers (Pay and conditions of service) Act, 2003 and the framing of H.P.Judicial Officers (Pay fixation) Rules, 2003, the following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Jr.Divn.) have been granted the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs.10750-300-13150-350 14900 with effect from the dates shown against their names:

Sr. No.	Name of the officer	Date of grant of 1 st ACP in the pay scale of Rs.10750-300-13150-350-14950
1	Shri Vivek Sharma	7.6.2007
2.	Shri Gaurav Mahajan	7.6.2007
3	Shri Naresh Kumar	10.6.2007
4	Smt Kanta Verma	6.6.2007
5	Shri Ranjeet Singh	11.6.2007

By Order OF THE HON'BLE
HIGH COURT OF H.P.
Sd/-
Registrar General

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA .

NOTIFICATION

Shimla, the 18th September 2007

No.HHC/GAZ/14-235/99-.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant ex post facto sanction of 3 days commuted leave w.e.f. 10.9.2007 to 12.9.2007 in favour of Shri P.S.Rana, Registrar (Inspection), High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Shri P.S.Rana has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri P.S. Rana would have continued to hold the post of Registrar (Inspection) but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 15th September, 2007

No.HHC/GAZ/14-297/07-.—In exercise of the powers vested under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H.P.Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, the Hon'ble High Court is pleased to extend the superannuation age of Shri Sher Singh Sen., a member of the H. P.Judicial Service in the cadre of

District/Additional District Judges, presently posted as District and Sessions Judge, Una, H.P. from 58 years to 60 years.

The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.

By Order OF THE HON'BLE
HIGH COURT OF H.P.
Sd/-
Registrar General

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 15th September, 2007

No.HHC/GAZ/14-297/07.— In exercise of the powers vested under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 14 of the H.P.Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling it in this behalf, the Hon'ble High Court is pleased to extend the superannuation age of Shri Pritam Singh, a member of the H. P. Judicial Service in the cadre of District/Additional District Judges, presently posted as Special Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh from 58 years to 60 years.

The officer will now retire on his attaining the age of 60 years.

By Order OF THE HON'BLE
HIGH COURT OF H.P.
Sd/-
Registrar General

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 15th September 2007

No.HHC/GAZ/14-99/80-II.— In exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 12 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004, the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh is pleased to order the confirmation of Shri Sachin Raghu, a member of H.P.Judicial Service in the cadre of Civil Judge (Jr. Divn.) with immediate effect.

The confirmation of the above Judicial Officer will not affect the interse seniority of the members of the H.P.Judicial Service of his batch, which shall be determined in accordance with the rules.

By Order OF THE HON'BLE
HIGH COURT OF H.P.
Sd/-
Registrar General

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2

सं० ए०एच०वाई-ए(३)-७/९९.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग में चालक वर्ग-।।। में (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग चालक वर्ग-।।। (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2007 है ।

(2) (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां .—(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या एएचवाई-ए(३)-८/९४ तारीख 26-06-1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग, चालक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नति नियम एतद द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन, के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम 2 (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप से की गई समझी जायेगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ता /—
सचिव ।

FORESTS DEPARTMENT**NOTIFICATIONS**

Shimla-2, 20th September, 2007

No. Van-A(F)6-2/92-I.— In suppression of this Department's notification of even No. dated: 9.1.2004, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Himachal Pradesh State Land Use & Wasteland Development Board as under:

1.	Chief Minister	<i>Chairman.</i>
2.	Forest Minister Ex-Officio	<i>Vice-Chairman.</i>
3.	Revenue Minister	<i>--do—</i>
4.	Agriculture Minister	<i>--do---</i>
5.	Sh. Surender Pal, MLA, Joginder Nagar	<i>Non-Official Member.</i>
6.	Sh. BBL Butail, MLA, Palampur	<i>--do—</i>
7.	Sh. Harsh Vardhan Singh, MLA, Shillai	<i>--do—</i>
8.	Thakur Kashmir Singh, Ex-MLA,	<i>VPO</i>
	Marhana, Tehsil Ghumarwin, district Bilaspur	<i>--do—</i>

9.	Thakur Nehar Singh, Ex-MLA, Kaloti, Tehsil Chirgaon, district Shimla	VPO --do—
10.	Chief Secretary, Government of H.P.	Official Member.
11.	Joint Secretary and Land Resource Commissioner Government of India (or his nominee)	--do—
12.	Pr. Secretary (Forests), Government of H.P.	--do—
13.	Pr. Secretary (Revenue), Government of H.P.	--do—
14.	Pr. Secretary (Agri.), Government of H.P.	--do—
15.	Pr. Secretary (Tourism), Government of H.P.	--do—
16.	Pr. Secretary (Plg.& Fin.), Government of H.P.	--do—
17.	Pr. Secretary (RD), Government of H.P.	--do—
18.	Pr. Secretary (PW), Government of H.P.	--do—
19.	Pr. Secretary (T&CP), Government of H.P.	--do—
20.	Pr. Secretary (Power), Government of H.P.	--do—
21.	Pr. Secretary (UD), Government of H.P.	--do—
22.	Pr. Secretary (S&T, Env.), Government of H.P.	--do—
23.	Vice-Chancellor, Agriculture University, Palampur.	--do—
24.	Vice-Chancellor, Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture & Forestry, Nauni, Solan,	--do—
25.	Pr. Chief Conservator of Forests, H.P.	--do—
26.	Director, Agriculture, H.P.	--do—
27.	Director, Industries, H.P.	--do—
28.	Director, Horticulture, H.P.	--do—
29.	Director, Environment, H.P.	--do—
30.	Director, Animal Husbandry, H.P.	--do—
31.	Chief Conservator of Forests, (Plg. & Dev.) H.P.	--do—
32.	Director, H.P. State Land Use & Wasteland Development Board, H.P.	Member Secretary

The duration of the board will be up to 3 years. The functions of the board shall be as under:

1. To assess the land resources of the State and the uses to which these resources can be put.
2. To consider all matters relating to soil conservation and water logging and salinity, intensive use of irrigation areas, maintenance of soil fertility and expansion of organization.
3. To lay down the policy for development and organizing the annual as well as periodical soil conservation and land management programmes including matter like training of personnel and conduct of research.
4. To provide a forum for bringing together various disciplines involved so as to involve integrated plans taking a sub watershed as unit.
5. To control and direct investigation including establishment of demonstration watersheds, survey and planning and soil conservations and land management works.
6. To examine periodically the progress of various results achieved to ensure proper implementation and to give such directions as deemed fit.
7. To provide a forum for sharing technical and administrative experiences which may be compiled and communicated to the public & field in the form of technical notes, bulletins, journals, publicity handcuts and films.
8. To examine and where necessary lay down standards and specifications of various types of works with a view to have sound and efficient planning and execution of the programme.

9. To examine from time to time the delegation of technical, administrative and financial powers in the Forest and Agriculture Departments for the efficient execution of the programme.
10. To collect, compile and furnish statistics pertaining to programme implemented in the state. In addition to the functions as detailed above, the Land Use Board shall also address itself to the following important points:
 - I. Review of existing land use in the state and exploration of possibilities of taking steps to putting lands to use according to their capabilities. This would inter-alia include programme such as Social Forestry (plantation of fuel and fodder trees), development of pasture etc in areas not fit for agriculture production.
 - II. Effective measures to be taken to protect good agriculture land against depletion on account of:-
 1. Soil Erosion due to wind, water and shifting cultivation.
 2. Water logging and salinity.
 3. Loss of fertility including micro-nutrients and
 4. Urbanization and industrialization.
 - III. Implementation of:-
 - (a) Command Area Development Projects.
 - (b) Dry land Farming Techniques.
 - IV. Reclamation of alkaline, saline, acidic soils and ravenous land.
 - V.
 - (a). Review of agriculture laws, in general, with particular reference to the problems relating to consolidation of holdings.
 - (b). Review of forests laws, with particulars reference to problems relating to protection and conservation of forest wealth, developmental aspects of forest resources etc.
 - VI. Identification of problems and bottlenecks in bringing culturable wastelands, fallow lands etc to crop productions. Promulgation and effective enforcement of land use statutes.
 - VII. Increasing land and water efficiency by adopting suitable cropping patterns, increasing intensity of cropping/irrigation.
 - VIII. Planning and survey of soil and water resources in selected blocks for their optimal utilization.
 - IX. Planning for integrated development of areas such as Diara/Khdar lands Kandi and arid areas.
 - X. Formulation and implementation of plans for rehabilitation of allottees of ceiling surplus land.
 - XI. Setting up of land reclamation and Development Corporation.

XII. Formulation and implementation of schemes for flood protection.

XIII. To create an informed public opinion in order to obtain their cooperation with regard to matters concerning better land and soil management.

XIV. To mobilize youth following Land Army concept for implementation of land and water use project.

11. Waste Land Development.

1. To formulate within the National and State Forest Policy, a perspective plan and programme and guidelines for development of wasteland/afforestation plan for the State.
2. To collect statistics and identify wastelands for afforestation purposes.
3. To act as a nodal agency for coordinating, funding and activities relating to different schemes of afforestation and wasteland development.
4. Review the progress and monitor/evaluate the implementation of programmes and schemes for development of wasteland by different agencies.
5. Approve afforestation and related projects for development of wasteland.
6. Collaborate with the Central and State Government Departments, agencies, local bodies and voluntary agencies with a view to mobilizing manpower, funds and other inputs required for afforestation and wasteland development.
7. Prepare budgetary requirements for the afforestation programme and interact with financial institutions for funding.
8. To fix afforestation targets and norms for afforestation and maintenance.
9. To set up expert group/inter disciplinary bodies for preparing projects/schemes on specified schemes.

The orders with regards to TA/DA to the no-official members, which have been issued earlier, shall remain operative.

Shimla-2, 2007

No. FFE-B-E(3)-76/96-loose.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute the Nature Conservation Society, Kullu, for the conservation of nature; watershed protection and infrastructure development in entire catchment area of river Beas and its tributaries in Kullu district.

The Society will function in accordance with the approved byelaws as annexed to this notification at Annexure-A.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

DEPARTMENT HORTICULTURE**NOTIFICATIONS***Shimla-2, the 17th Sept., 2007*

HTC-F (5)-2/2007-Loose.—In partial modification to this department notification number HTC-F (5)-2/2003 dated 22-9-2003, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Additional Chief Secretary (Hort.) to the Government of Himachal Pradesh as Chairman of State Level Steering Committee of Horticulture Technology Mission in place of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh with immediate effect.

HTC-F (5)-2/2007-Loose.—In partial modification to this department notification number HTC-F (5)-2/2003 dated 22-9-2003, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Additional Chief Secretary (Hort.) to the Government of Himachal Pradesh as Chairman of State Level Steering Committee of Horticulture Technology Mission in place of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh with immediate effect.

By order,
RAVI DHINGRA,
Chief Secretary

File No. HTC-F(5)-2/2003-Vol-II

From

The Principal Secretary (Hort.) to the
Govt. of Himachal Pradesh

To

1. The Director Horticulture, HP Shimla-2
2. All the Deputy Commissioners, in Himachal Pradesh.
3. The Project Directors, HTM, Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Directors of Horticulture in Himachal Pradesh.

Date th May, 2004 Shimla-2

Subject: Clarifications on the guidelines for implementation of schemes under Horticulture Technology Mission.

Sir,

I am directed to say that the Horticulture Department is implementing the Horticulture Technology Mission sanctioned by the Govt. of India in the State. The Govt. India has issued guidelines for its implementation. Based on these guidelines the Horticulture Department has further issued detailed guidelines to the field functionaries and other concerned officers for its smooth and effective implementation. However, it is observed that the field functionaries have not understood these guidelines in true spirit as is clear from the poor progress of the implementation of

different schemes under Horticulture Technology Mission and various clarifications being sought by the field officers from time to time. The matter has been under active consideration of the Govt. for some time and in order to expedite the implementation and accelerate the progress of various schemes under Horticulture Technology Mission at the field level, the State Govt. issues following further clarifications to the guidelines for implementation of Horticulture Technology Mission:

1. The definition of Horticulture is broad based which includes productions, marketing and processing of fruits, flowers, vegetables, plantation crops, herbs, spices, aromatic plants etc. any scheme relating to aforesaid definition of Horticulture can be covered under HTM.
2. All the schemes under HTM should have vertical and horizontal integration i.e. a beneficiary can combine all the components of scheme under one project.
3. There should be convergence and synergy amongst number of on going governmental programs. At present some other Govt. Departments are also implementing schemes/ programs related to Development of Horticulture e.g. Agriculture, Forest, RDD, some external aided projects etc. These schemes can be integrated with the schemes of HTM and a grower/promoter can avail benefit from all concerned schemes / programs to the extent of 50% of the project cost and the balance funds shall be arranged by him either from financial institutions or from his own resources like labour, farmer inputs, borrowings etc. It is more important with the background that the horticultural sector is capital intensive and its produce is highly perishable. We need to encourage hi-tech methods for commercial production of Horticultural crops, post harvest management, cool chain infrastructure, primary processing units etc.
4. If the farmer has Kisan Pass Book and he reproduces the attested copies of the land records entered in the pass book, there should be no need to ask for other land document like *Jamabandi* and *Tatima* etc. The Kisan Pass Book should suffice the purpose or a certificate supporting the ownership of land by the Patwari of concerned area should fulfill the purpose. The bond forms and affidavits in case of individual farmers are not required except in case of joint property, NGO, Society or Panchayat. The main objective of this mission is to encourage the farmers to take up horticultural activities.
5. Application form has been devised to obtain benefit under technology mission, which should serve the purpose to the fullest. Copy of the form enclosed as annexure –2

Program wise further clarifications under horticulture technology Mission:—

(a) *Area Expansion:* Under this program the assistance will be provided for the cultivation of fruits like apple (spur, colour strains & Processing varieties) Pear (Color strains) Plum (Newly recommended Var) Peach, Hectarines, apricot, Prunes, Cherry, Pomegranate, Hazel Nut, Walnut, Pecan Nut, Aonla, Mango Litchi, Kiwi, Ber Guava, Citrus (Sweet Orange, Kinnow, K. lime) Vegetables including root & tuber crops, exotic vegetables and Vegetable Hybrids, Flowers, Spices, Medicinal & Aromatic plants, plantation crops etc.

For the planing of new orchards/ replanting of old orchard, the farmer will be eligible to get assistance for the purchase of planting material, preparation & development of land (uprooting of old Trees/ leveling/ ploughing etc.), fencing of area with locally available material, digging of pits,

laying out of orchard, purchase of FYM, inter culture operations and even if required the water tank for irrigation purpose. The assistance will remain Rs. 13,000 per Ha.

(b) *Creation of Water Source:* This scheme could be extended to the individual farmers besides community water storage tanks suiting to the local topography and demand, for storage of water of the capacity as per their requirement and as per norms. For Drip and Sprinkler irrigation moulded plastic tank with capacity of not less than 2500 litres can be provided.

(c) *Plasticulture:* The firms should be identified and registered at the Director level, so that the field officers do not have difficulty in directing the farmers to the firms for installation of Drip/Sprinkler irrigation systems and Green Houses. Directorate will finalize the list of firms on the basis of merits and quality parameters. Since UV sheets is the most important component in installation of green houses & quality of the UV sheets has to be ascertained. Therefore Department of Horticulture will take rigorous exercise in identifying the manufactures of UV sheets. An assistance of National Plastic Application Center be taken for identifying the manufactures of the UV sheets.

(d) *Anti hail nets :* At present there is a provision to provide anti hail nets to cover 50 trees @ 50% assistance with max limit of Rs. 500/- per tree with the total assistance of Rs. 25,000, it has now been decided that maximum benefit for antihail net should not exceed Rs. 25000 per farmer whereas number of nets can increase depending upon the prevailing rates in the market.

(e) *Popularization of Organic Farming:* The size of Vermi-compost unit will depend upon the size of holding and requirement of the farmer. The assistance on construction of Vermi-compost unit will be limited to 50% assistance of the total cost or maximum to Rs. 30,000/-. However, Vermi-compost unit be constructed as per design and structure evolved by HPKVV Palampur.

(f) *Beekeeping:* In order to promote bee keeping with the twin objective of honey production and pollination it has been decided that a unit of 100 bee colonies be provided to the trained bee keeper. The rate of assistance per colony and per hive will remain the same as indicated in the guidelines. The source of bee colonies should be the registered breeder of the Department.

(g) *Tools/implements:* Assistance to the farmers may be granted for purchasing tools and implements of any type, quality, and design from open market within limit of assistance as per guidelines.

(h) *Fencing:* Fencing is the critical input for any orchid. The department may allow fencing of any kind like iron, interlink chain barbed wire, solar, electric, biofencing etc. within overall limit.

(i) *Centre of Excellence under Horticulture:* At least one Centre of excellence in each Distt. Should be established. These Centres of Excellence would serve as demonstrations on integrated Development of Horticulture. Each Deputy Director of Horticulture will prepare a project report concerning to his Distt covering all components of the mission including MM I, MM II, MM III, MM IV. For better performance in establishment of Centre of excellence outstanding officers will be rewarded.

j) *Maintenance and upkeep of the record and monitoring:* Transparency is one of the foremost requirement for successful implementation of any scheme which should be observed at every level. There is need to keep & maintain the record of all beneficiaries and the spot inspections carried out by the various officers at Block level as well as District level. Inspection

registers shall be maintained at each Block Headquarter and the officers should append the inspection report in these registers in addition to the inspection report sent to Deputy Director's office.

The HDOs shall submit the progress report scheme wise giving the name of beneficiaries along with the amount sanctioned / released for the month by 7th of next month to the Deputy Director concerned. The Deputy directors shall compile the Block-wise report and submit the progress report the directorate by 15th of the month. The directorate shall submit quarterly progress report schemewise and District-wise to the Government by the end of next month after the quarter ended.

(k) *Time frame for release of subsidy:* The HDO shall visit the spot within 30 days of receipt of information about the completion of scheme by the beneficiaries. He shall record his inspection note in the register maintained at Block level and send a copy of the same to the Deputy Director concerned alongwith recommendations. In case of projects involving financial assistance above Rs. 5.00 lacs the DHO/SMS shall visit the spot and submit the report to the Deputy Director. For this purpose the Deputy Director shall allocate the area to the concerned officer. However, in other cases the DHO/SMS shall inspect not less than 25% of the schemes.

On receipt of inspection report /recommendations the Deputy Director office shall release the subsidy within 15 days from the date of the inspection by way of Demand Draft/ Cheque in favour of the beneficiaries preferably through registered post. Information to this effect shall be sent to the HDO concerned for information and records.

The Project Directors shall invariably inspect some of the schemes during their visits to Districts and fields.

(l) *General:* The release of assistance under infrastructure building like water storage Tanks, installation of green houses, drip irrigation, on farm handling unit, and vermin-compost unit etc. can be staggered over two installments in order to facilitate the construction/ installation works. Those beneficiaries who have already created the above assets and their assistance has not been released till date, be immediately released after verifying the asset, without causing any inconvenience to the beneficiary. Efforts be made that the projects, which are linked with the bank loan, the assistance, is adjusted towards the loan repayments.

District Level Coordination committee has been constituted to facilitate the Departmental efforts for the development of Horticulture and to see if the convergence of schemes being run by other departments could be done for the same purpose at District level. DCC at random should keep check on implementation of the mission by visiting the beneficiaries and verifying the infrastructure/ benefits availed by the farmer.

Procedural complications have to be minimized/ simplified and Deputy Directors of Horticulture will keep the DCC apprized about the list of beneficiaries and kind of benefits given to the farmers. In fact DCC should work as facilitator and should help the Department in successful implementation of the mission. Programs of the mission are to be implemented as per given guidelines in letter and spirit.

Yours faithfully,
Joint Secretary.

COMPONENT UNDER WHICH ASSISTANCE REQUESTED:—

1. *Area Expansion:* Fruit Plantation, Vegetable, Floriculture, Medicinal & Aromatic Plants, Spices and Tuber Crops.
2. *Creation of water sources:* Community/ Individual Storage Tank.
3. *On farm water management:* Drip/Sprinkler Irrigation, Plastic Mulching, Green House, Low Tunnel, Shade Net, Anti hail Nets, Anti Bird Nets.

4. *On farm Handling Units:* To create facility for storage and handling of produce at farm level.
5. *Production of Planting material:* Integrated Multi Crop Nursery, Small Nursery , Progeny and Herbal garden, Tissue Culture Unit.
6. *Transfer of Technology:* Training with in State, Training Outside State.
7. *Organic Farming:* Adoption of Organic Farming, Vermi Compost Units, Certification of Organic Produce.
8. *Promotion of Agriculture equipments:* Manual, Power tiller, Power Operated, Diesel Engine.
9. *Integrated Pest Management:* Use of Bio pesticide(Ha).
10. Development of bee Keeping: Bee Colonies and Hives, Migration, Promotion of Bee Breeder.
11. Entrepreneurial Development of Women Farmer: Training, Self Help Group.

TOTAL COST ESTIMATE
OF THE PROPOSAL FOR ALL
COMPONENTS

Rs. _____

2. I/we certify that the particulars furnished above by me /us are true to the best of my/ our knowledge and belief that nothing has been concealed there in.

3. I/We give an undertaking to the effect that the Department of Horticulture and other concerned agencies shall have the right to inspect the material purchased/ quality of the material and work done.

4. In case of misutilization or non utilization of assistance in whole or part, I/ we under take to refund the amount of assistance granted to me / us in full and in lump-sum , along with the interest at the prevailing Bank rates thereon.

Yours Faithfully,

Name and Address of the Applicant.

Application along with project proposal/ relevant documents for assistance to the extent of Rs. _____, is forwarded to the Deputy Director of Horticulture Distt. _____, Himachal Pradesh for consideration and onward transmission to the Director of Horticulture, Himachal Pradesh.

Horticulture Development Officer,
Dev. Block/ Ext. Centre _____.
Distt. _____, HP

Countersigned / recommended
Dy. Director of Horticulture, Distt. _____.
Himachal Pradesh.

Production related activities:

High quality commercial horticulture crops/produce
 Roof-top/terrace gardens
 Indigenous crops/produce, herbs, spices
 Aromatic and medicinal plants
 Seed and nursery
 Bio-technology, micro-biology, bio-chemistry
 Bio-diversity, tissue-culture, mist chambers
 Bio-pesticides
 Organic fertilizers, organic foods, bio-dynamic
 Farming and vermi compost
 Establishment of horticulture Health clinics and laboratories
 Consultancy services
 Beekeeping and its products
 Nuts and its products.

Use of Plastics:

Green Houses
 Poly Houses
 Shade nets
 Bird Protective nets
 Antie-hail nets
 Low tunnels miniature green houses
 Polyench developed by DRDO for Leh/Ladakh.

Water harvesting facilities:

Concrete structures
 Earthen water storages
 Dig wells
 Sink wells
 Tube wells
 Lifting of water from spring sources, streams, Nallahs, Rivers through pumps
 Drip and Sprinkler systems
 HDEPE tanks with capacity above 2000 ltrs.

(The above mentioned components may also include the cost of accessories, tools, equipment and power pumps).

PHM and Primary Processing Related activities

Grading, packaging, washing, waxing, sorting, drying (including solar)\
 Sizing, palletizing units
 Cold storages, Controller atmosphere and Modified atmosphere Cold storages
 Pre-cooling units, cool stores
 Zero Energy Cool-Chambers, hydro-coolers, Reefer Vans, containers (with multy Product Facility)
 Specialized Transport Vehicles

Retail outlets
 Auction platform
 Ripening curing chambers
 Market yards, rope ways
 Irradiation, Dehydration, vapor Heat treatment units
 Freezing units machines etc.
 Natural colour dyes extraction
 Essential oils, perfumery and cosmetics out of horticulture products
 Products out of horticulture wastes
 Farm equipments, Water lifting pumps machinery, plastics, packaging etc.
 Crates, cartons, Aseptic packaging and shade and anti-hail Nets.
 Quality Assurance Systems (HACCP, T.Q.M, ISO, ISO EUREPAGAP etc)

Primary processing of products e.g. fermentation Extraction, distillation, vending, pulping, dressing, cutting, chopping Clarifications being sought by the field officers from time to time. The matter has been under active consideration of the Govt. for some time and in order to expedite the implementation and accelerate the progress of various schemes under Horticulture Technology Mission at the field level, the State Govt. issues following further clarifications to the guidelines for implementation of Horticulture Technology Mission. It is further clarified that the schemes have been so structured that their implementation becomes flexible and therefore the guidelines issued earlier and now are only broad road maps, which should not be interpreted in letter and spirit. As specifically mentioned in the guidelines of Mini-Mission II, these schemes should be implemented on cluster approach, i.e. to focus and concentrate in pockets, which will have a demonstrative effect on others. The field officers should avoid tendency to interpret these guidelines as instructions of the Govt., which is not the case. The overall objective is to make the entire Horticulture sector more dynamic by integrating all the schemes together.—

1. The definition of the Horticulture is broad based which includes high-tech commercial production, post-harvest management, Cold chain ,primary processing and marketing of all types of fruits, flowers, vegetables, plantation crop, herbs, spices, aromatic plants, etc. The details of some of the crops may be glanced at (Annexure-I). It is emphasized that this list is not exhaustive but suggestive. There may be many more crops(including those growing in the wild) which can be included for assistance for promoting hitech commercial horticulture under the Horticulture Technology Mission. Activities which are covered under Post harvest Management, cold chain etc., are broadly contained in Annexure-II) Therefore any scheme relating to aforesaid definition of Horticulture can be covered under Horticulture Technology Mission.

2. All the schemes under HTM should have a vertical and horizontal integration i.e. a beneficiary can combine the components of various schemes under one proposal/project. However, State Govt. has a discretion to give special thrust to some of the crops/activities keeping in mind demand and supply position within the domestic or external markets and also the suitability according to the appropriate agro- climatic conditions prevailing in various locations within the State.

3. There should be convergence, synergy amongst the number of on-going governmental programs both of Govt. of India and State Govt. including MP/MLA funds. At present other Govt. departments are also implementing schemes/programs related to development of horticulture e.g. agriculture, forest,RDD, I &PH some external aided projects etc. If these departments/organizations have no objection to the convergence of their schemes then these schemes can be integrated with the schemes of HTM. In that case, grower/promoter can avail the benefits from all concerned schemes/program to the extent of 50% of the project cost and the balance funds shall be arranged

by him either from the financial institutions or from his own resources like labour, farmers input, borrowing etc. It is desirable because horticultural sector is more capital intensive than any other activity under agriculture produce and horticulture produce is highly perishable. We need to encourage hi-tech methods for commercial production of horticultural crops, post harvestment, cool chain.

provided within overall financial limits. The farmers may exercise option either to avail assistance for one or more such activities within the prescribe limits.

- (b) *Creation of Water Source:* This scheme could be extended to the individual farmers besides community water storage tanks suiting to the local topography and the capacity for storage of water i.e. concrete structures, earthen water storage, dig-well, tube wells, sink well, lifting of water from the nearby springs, streams, Nullahs rivers through pumps etc. as per their requirement. If in a command area of one hect.more small farmers are interested to construct such water storage facilities with total capacity of 3,00,000 liters (Three lacs liters), then the total assistance amount will remain Rs.1.00 lac only and assistance amount will be distributed proportionately amongst all the farmers as per the capacity of their tanks, which will ultimately justify the community needs. Maximum command area in this regard as given in the guidelines could be 10 hect and assistance amount will Rs.10.00 lacs on the basis of above mentioned criteria. For Drip and Sprinkler irrigation, moulded plastic/HDPE tanks with a capacity more than 2000 liters can be provided.
- (c) *Plasticulture:* The firms which are already identified and registered at the Directorate level or such suppliers already identified by IHBT, Horticulture Division, GOI, Department of Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Nauni, Solan, Agriculture University Palampur, S & Transaction, GOI, ICAR, Directorate of Agriculture, HP can also be entertained. Of late, cost of iron and plastic and other materials have increased considerably. Therefore, suggestions are often received that the growers/promoters may be allowed to fabricate green houses locally. They may be encouraged to undertake such an effort. Use of Bamboo should be encouraged. Any guidance about the latest trends and innovativeness may be obtained from the National Plastic Application Centre.
- (d) *Anti hail nets:-* At present there is a provision to provide anti hail nets to cover 50 trees @ 50% assistance with maximum limit of Rs.500/- per tree with the total assistance of Rs.25,000/-. It has now been decided that maximum benefit for anti-hail net should not exceed Rs.25,000/- per farmer whereas number of nets can increase/decrease depending upon the prevailing rates in the market.
- (e) *Popularization of Organic Farming:* The size of Vermi-compost (organic) units will depend upon the size of holding and requirement of the farmers/promoters. The assistance on construction of Vermi-compost units will be limited to 50% assistance of the total cost or maximum to Rs.30,000/-. However, Vermi-compost unit be constructed as per design and structure evolved by HPKVV Palampur or any other agency or organization. If the jurisdiction of a block either overlaps or a part of which falls in another Sub-Division, the SDM shall entertain only such cases which falls within the area of his jurisdiction of the part of that block.
- i) The Block Level Committee is empowered to sanction and release the funds under the Mini Mission II upto Rs.5 lacs under each project proposal of the Mini Mission.

- (ii) The HDO concerned shall verify the Proposals within 15 days of its receipt. The inspection/verification of the Proposal of the individual will be made by the HDO concerned and he should associate the Ward Member of the Panchayat or Pradhan of the Panchayat, before submitting the proposals to the Block Level Committee.
- (iii) The Block Level Committee shall meet once in a fortnight. The members of the Committee may carry out random inspection and verification of the Proposals.
- (iv) Deputy Director, Horticulture shall replenish the funds to the block –level committee from time to time.
- (v) Single project proposals above Rs.5.00 lacs to 10 lacs shall be considered and sanctioned by the Deputy Commissioner or his representative of the concerned district in the District Level Coordination Committee every fortnight. The committee may also review the implementation schemes at the block and district level. All the Deputy Directors (Hort.) may examine such proposals which will be placed before the District level committee. One officer of the office of Dy. Director Horticulture shall act as a member Secretary. Funds may be released promptly to the beneficiaries.
- (vi) Individual project proposals involving a financial outlay of above Rs.10 lacs shall be considered by the Project Directors, Horticulture Technology Mission. Also, Integrated Projects involving Mini Mission II, III, and IV and schemes under Centre of Excellence under horticulture shall also be considered by the Project Directors (HTM). Proposals above Rs.10 lacs shall be framed with the help of Consultants before being submitted to the Project Directors. Such proposals shall be processed by the following committee:—

(a) Project Director	<i>Chairman</i>
(b) Deputy Director (Marketing)	<i>Member Secretary</i>
(c) Representative of hpmc	<i>Member</i>
(d) Representative of Financial Institution/Bank concerned	<i>Member</i>

The above Committee shall meet within 15 days and either recommend the project proposals to various agencies of Govt. of India for Mini-Mission- III&IV or place before the Single Window Committee, Deptt. of Industries, HP, under the Thrust Sector industries and specified category of industries of the new industrial policy.

- vii) Every proposal submitted for obtaining assistance under the Horticulture Technology Mission should enclose a certificate that the Project/ beneficiary has received no assistance for the same purpose from the Block level committee or the District Level Committee.

Yours faithfully,
Principal Secretary.

HORTICULTURE DEPARTMENT**Subject: Regarding Meeting Conference etc. about HTM.****Dy. No. 1404, Page-1.**

PUC-1: The Cabinet Secretary New Delhi vide letter at P-1 has intimated that a conference of Chief Ministers of all States and Union Territories will be held on 15th April, 2005 in New Delhi. The venue of the conference will be Vigyan Bhavan. The conference shall have the following agenda items.—

Forenoon Session:—

1. Presentation on and launch of the Rural Health Mission, the Urban Renewal Mission and the Horticulture Mission followed by discussion on these Missions.
2. Presentation on the various developmental programmes comprising the “Bharat Nirwan” initiative followed by discussion.
3. The role of States in integrating Science and Technology into their development agenda.

Afternoon Session:—

Law and order issues with particular focus on extremist activities.

This is advance information for the appraisal of Hon'ble Chief Minister and detailed programme is awaited.

In this connection, it is submitted that Horticulture Mission is related to Horticulture Development which is being launched in the conference of the Chief Ministers of all States and Union Territories on 15-4-05 in the Vigyan Bhavan, New Delhi.

A status note of Horticulture activities and Scheme/Programme being implemented in Himachal Pradesh is also placed below.

Submitted please.

N-89:—As desired by the Principal Secretary Horticulture at N-89 ante, the self-contained note regarding the resumption of land allotted to HPMC on lease basis at Salt Lake City Kolkatta is as under:—

In Concise, it is submitted that a piece of land measuring 1500 square meters was allotted by the West Bangel Govt. at Salt Lake City Kolkatta in 1988 for the construction of the Cold Storage. The allotment order (may be seen page 109-110) and the lease deed for 999 years of this plot may be perused at page 109 corrs. The letter of delivery of possession of land given by the West Bangel Govt. may be seen at page 108 corrs. However over the years, several attempts to construct the Cold Storage by the HPMC themselves or other private party failed. Meanwhile, the area of Salt Lake was developed as an Electronic Complex by the West Bangel and the West Bangel Govt. wanted to resume this vacant land and re-allotted to same other parties on the ground that it continues to remain vacant ever after fifteen years. Therefore, the HPMC succeeded in

obtaining stay from the Hon'ble Second Civil Judge Barasat dated 31-8-2004. The Hon'ble Court has restrained from dispossessing the HPMC from the suit property, which may kindly be seen at page 118 corrs.

The Govt. of West Bengal have failed to resume the land due to Court intervention. Therefore the Govt. of West Bengal has offered to take plot of land of equal size of even more in new township at Rajarhat in lieu of plot at Salt Lake Kolkatta which may kindly be seen at page 16 corrs.

In view of above offer, the HPMC has sent its willingness to take an alternative land at Rajarhat to the Govt. of West Bengal vide letter at page 26 corrs. In response to our willingness, the West Bengal Govt. has issued a letter of NOC for providing an alternative plot at Rajarhat with the condition that the HPMC has to pay the existing market price vide letter at page 29 (Dated 18-11-2005)

In view of the condition of West Bengal, a letter from Hon'ble Chief Minister of H.P to the Chief Minister of West Bengal was issued at page 30-31, requesting that the plot at Rajarhat may be allotted in favour of HPMC in exchange of plot at Salt Lake.

In response to our letter at page 30-31, Hon'ble Chief Minister of West Bengal vide letter at page 33 has informed that the matter is being looked into. Thereafter the reminder was also issued to Hon'ble Chief Minister of West Bengal at page 39 in response to our letter at page 39. The Hon'ble Chief Minister of West Bengal has again informed vide letter at page 52 that the matter has been referred to the appropriate authority for early decision. Now, the Chief Secretary of West Bengal has written a letter to the Chief Secretary of H.P to intervene in the matter and hand over the possession of land at Salt Lake to the Govt. of West Bengal without providing an alternative land to HPMC at Rajarhat and offered to allot another plot of land to HPMC at a suitable location for construction of their Cold Storage and also to requested to depute officer for inspecting of plots in exchange of plot at Salt Lake which may kindly be seen at page 60-61.

In view of the request of the West Bengal Govt. Sh. Suriender Mohan SMO HPMC was deputed to inspect the alternative land at Kolkatta. The said officer visited Kolkatta from 21st December to 24th December 2004. In connection with the inspection of alternative site. From the perusal of the report submitted by the said officer at page 71 it has been gathered that the reporting officer is of the opinion that in view of the prime location Commercial Value and other aspects, the land should not be surrendered at any cost. Simultaneously the Chief Secretary to the Govt. of H.P directed the Resident Commissioner of H.P New Delhi to visit Kolkatta in connection with the land of HPMC at Salt Lake City and discussed the matter with West Bengal Govt. After visiting Kolkatta, the Resident Commissioner, Govt. of H.P New Delhi submitted detailed report vide letter at page 85-89.

After going through the report of the Residential Commissioner New Delhi, it has been gathered that the cities shown to him by the West Bengal Govt. are not acceptable due to either disputed site or there would be problems in taking over possession of the land from the villagers being physically occupied for breeding fishes and paddy cultivation.

The Residential Commissioner has finally recommended that the existing plot of land at Salt Lake Kolkatta should not be returned to the Govt. of West Bengal as the present land is invaluable as on today being situated in the heart of Salt Lake City. It is pertinent to mention here that Executive

Engineer at Municipal Corporation Kolkatta vide letter dated 20-5-2005 at page 120 has allowed HPMC to go ahead with the construction of the building up to ground level. It is also submitted that Hon'ble High Court does not bar HPMC from the construction of a boundary wall around the existing plot moreover, sanction of building plan are valid till August 2005 and the construction of boundary wall of the plot should be started before the date. The Worthy Chief Secretary of H.P being well conversant of the case has requested the Chief Secretary of the West Bangal vide letter at page 104-106 that the existing plot at Salt Lake can be return to the West Bangal Govt. Only if the land at Rajarhat in exchange of existing plot is given to HPMC. As the plot at Rajarhat is acceptable to the HPMC. The reply of the West Bangel Govt. is still awaited in the matter.

It is also pointed out here that the office has recently received a copy of notification date 6-5-2005 issued by the Urban Development Deptt; Government of West Bangal whereby they have allowed a lessee or transferee of lease hold right to change the old project for which the land was allotted in sector -V and out side sector-V of Bidhan Nager. It implies that the Govt of West Bangel does not intend to cancel any lease deed. (See page 121-123)

Submitted for the perusal of the Hon'ble Chief Minister

S.O (Hort)

Additional Secretary (Hort)

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2007

संख्या एल0एल0आर0-11/2007-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का, प्रयोग करते हुए दिनांक 20-09-2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 11) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
जे0एन0बारोवालिया
प्रधान सचिव।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 सितम्बर 2007 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो.—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

2. **धारा 185 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (1994 का 4) 185 में.—

(क) उपधारा (2) के खण्ड (क) में “मन्त्री” शब्द के पश्चात् “या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) में, “तथा उपायुक्त/जिला मेजिस्ट्रेट” शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.—

“(4) सम्बद्ध जिला का उपायुक्त, समिति का सचिव होगा।”

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No 15 of 2007

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ
(AMENDMENT) ACT, 2007**

AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH SEPTEMBER, 2007

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

Be it enacted by the legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Fifty-eight Year of the Republic of India as follows.—

1. **Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2007.

2. Amendment of section 185.—In section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, (4 of 1994) 1994.—

- (a) in sub- section (2), in clause (a), after the word "Minister", the words " or Speaker or Deputy Speaker" shall be inserted;
- (b) in sub-section (3), the words and sign" and the Deputy Commissioner/District Magistrate" shall be deleted; and
- (c) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely.—

"(4) The Deputy Commissioner of the District concerned shall be the Secretary of the Committee."

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 22 सितम्बर, 2007

संख्या एल०एल०आर०—डी०(६)—११/२००७ लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-09-2007 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2007 (2007 का विधेयक संख्यांक 11) को वर्ष 2007 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
जे० एन० बारोवालिया,
प्रधान सचिव ।